

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,
(सामान्य) वन मंडल, राजगढ़,
मध्यप्रदेश।

विषय:—राजगढ़ जिले में ग्रामीणों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मोहनपुरा बहु ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के अन्तर्गत पीने के पानी की टंकी के निर्माण हेतु 0.63 हेक्टेयर वन भूमि म0प्र0 जल निगम मर्यादित, PIU राजगढ़ को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:— (1) इस कार्यालय का पत्र क्र0/एफ-5/897/2019/10-11/956 दि0 07.03.2020
(2) महाप्रबंधक, म.प्र.जल निगम मर्यादित, राजगढ़ का पत्र क्रमांक/मा.चि./494/पीआईयू/2020 दिनांक 11.05.2020

—0—


उपरोक्त संदर्भित पत्र (1) द्वारा विषयांकित प्रस्ताव में इस कार्यालय द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई थी। संदर्भित पत्र (2) द्वारा आवेदक संस्थान ने विषयांकित प्रकरण में जारी सैद्धांतिक स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को भेजा है। पालन प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक संस्थान द्वारा प्रकरण में नेट प्रजेण्ट वैल्यू की राशि रु0 3,94,380/- एवं राशि रु0 100/- ई-पोर्टल के माध्यम से भुगतान कर दी गई है तथा आवेदक संस्थान द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन भी ई-पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

अतः सैद्धांतिक स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन के आधार पर औपचारिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

- 1- Legal status of the forest land shall remain unchanged.
- 2- Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency.
- 3- User agency shall restrict the no felling of trees.
- 4- The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
- 5- No labour camp shall be established on the forest land.
- 6- User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.
- 7- The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.

- 8- No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
- 9- The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
- 10- No work shall be done during night.
- 11- The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
- 12- Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11- 42/2017-FC dt 29/01/2018.

उपरोक्तानुसार समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन आवेदक संस्थान से प्राप्त कर प्रकरण में आवेदक संस्थान को कार्य करने की एवं क्षेत्र हस्तांतरण की अनुमति दी जावे।


09/07/2020
(सुनील अग्रवाल)


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबन्ध)
मध्य प्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ-5/897/2019/10-11/2141

भोपाल, दिनांक 9-7-20

प्रतिलिपि:-

- 1- मुख्य वन संरक्षक, भोपाल वृत्त, भोपाल, मध्यप्रदेश।
- 2- महाप्रबंधक, म0प्र0 जल निगम मार्यादित, PIU, बी-5, भंवर कॉलोनी, राजगढ़, म0प्र0।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


09/07/2020
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबन्ध)
मध्य प्रदेश, भोपाल